प्रकाशनार्थ

पटना, 1 अक्तूबर। ''15वें वित्त आयोग की अनुशंसा करते समय बिहार के लिए सहानुभूति नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।'' यह बात 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह ने आज पटना में कही। श्री सिंह आद्री द्वारा आयोजित ''भारत में राज्यों और जिलों के बीच मौजूद विषमता की समस्या का निवारण'' विषय पर आयोजित एकदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में 150 की संख्या में मौजूद शिक्षाविदों, शीर्ष व्यवसायियों, राजनेताओं, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा बुद्धिजीवियों को संबोधित कर रहे थे।

आयोजन में अतिथियों का स्वागत करते हुए आद्री के सदस्य-सचिव डॉ. शैबाल गुप्ता ने कहा कि ''राज्यों और जिलों के बीच विकास के मामले में विषमता अकादमिक विषय भर नहीं है। यह विकास के लिए गंभीर चुनौती है और इस विषमता में कमी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरणों, शिक्षाविदों, प्रोफेशनल, नागरिक समाज संगठनों, मीडिया और अन्य लोगों जैसे विभिन्न स्रोतों की प्रतिक्रिया जरूरी है।''

श्री गुप्ता के बाद बिहार सरकार के वित्त विभाग की प्रधान सचिव सुश्री सुजाता चतुर्वेदी ने संगोष्ठी के मुख्य उद्देश्यों को रेखांकित किया और कहा कि ''विचार-विमर्श में पिछड़ापन के विभिन्न कारणों को चिन्हित किया जाना चाहिए ताकि वे योजनाकारों को क्षेत्र आधारित विकासमूलक रणनीतियां चिन्हित करने में मदद करे। संगोष्ठी में संतुलित विकास पैटर्न को बढ़ावा देने में केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका पर भी चर्चा की जाएगी।''

झारखंड के संसदीय कार्य तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सरयू राय ने कहा कि '' उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए हमेशा ही एक परिषद रहा है जो सातो राज्यों में विकास की दिशा में काम करता है लेकिन पूर्वी राज्य ऐसे फोकस से हमेशा वंचित रहे हैं।'' श्री राय ने यह भी कहा कि ''पूर्वी भारत में प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी (अब बिहार इसका अपवाद है) के बावजूद अधिसंरचनात्मक सुविधाओं के मामले में भारी कमी है। पंद्रहवां वित्त आयोग अगर इन राज्यों के लिए अनुकूल अनुशंसाएं करे तो उससे इन राज्यों को भारी मदद मिलेगी''।

ASIAN DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTE
BSIDC Colony, Off Boring-Patliputra Road, Patna - 800 013, Tel. : 0612-2575649, Fax : 0612-2577102
E-mail : adripatna@adriindia.org / adri_patna@hotmail.com, Website : www.adriindia.org

हिंदी में दिए गए अपने उद्घाटन भाषण में श्री एन.के. सिंह ने कहा कि बिहार के विधान सभाध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में जो भी कहा है वह राज्य की पूरी जनता की आकांक्षाओं की सच्ची अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों को 15वां वित्त आयोग 'बहुत जटिल' पा रहा है, वे वस्तुत: अभी तक के सभी वित्त आयोगों के लिए बहुत जटिल रहे हैं। उन्होंने इस बात को भी प्रमुखता से सामने रखा कि इटली जैसे देशों के ऐतिहासिक अनुभव उन समस्याओं को समझने में बहुत उपयोगी है जिनका सामना बिहार और ऐसे अन्य राज्य कर रहे हैं। श्री सिंह ने अपनी वित्तव्यवस्था में कुशलता लाने और व्यवस्थित करने के लिए देश में चल रही ढेर सारी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन करने की भारी जरूरत पर बल दिया।

यह कहते हुए कि 15वें वित्त आयोग के लिए 'विचारार्थ विषय' में भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 का अनुसरण किया गया है, उन्होंने बताया कि संसाधनों के विभाज्य कोष पर वित्त आयोग के निर्णय में उपलब्ध संसाधनों और देशव्यापी मांगों के बीच संतुलन रखने का प्रयास किया जाएगा। श्री सिंह ने समवर्ती सूची के विस्तार पर चिंता प्रकट की और सातवीं अनुसूची के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की जरूरत जतलाई।

श्री एन.के. सिंह के पहले बोलते हुए बिहार के विधान सभाध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि यह आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए निहायत जरूरी होगा। बिहार के लिए 'विशेष श्रेणी' की प्रस्थिति (स्टेटस) की मांग पुन: उठाते हुए श्री चौधरी ने कहा कि ''अगर बिहार की भौगोलिक (जो राज्यों को यह प्रस्थिति देने का शीर्ष मापदंड है) बनावट पर विचार किया जाय, तो राज्य इसके लिए सर्वाधिक अनुकूल है''।

आद्री के निदेशक प्रभात पी. घोष ने इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन किया।

(अंजनी कुमार वर्मा)

ASIAN DEVELOPMENT RESEARCH INSTITUTE
BSIDC Colony, Off Boring-Patliputra Road, Patna - 800 013, Tel. : 0612-2575649, Fax : 0612-2577102
E-mail : adripatna@adriindia.org / adri_patna@hotmail.com, Website : www.adriindia.org